सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com swarajindianews swarajindianews

दैनिक सांध्यकालीन

स्वराज इंडिया

कानपुर, शनिवार, 25 अक्टूबर, 2025
वर्षः 02, अंकः 283, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

इनसाइड छठ से पहले घाटों की बदहाली, नमामि गंगे के दावे... » Pg04

» Pg12

सरकार का फैसलाः पूरे प्रदेश में होगी नकली दवाओं की जांच

यूपी सीएम की कार्यशैली में सख्ती, 2027 की चुनौती

योगी को संघ व संगठन की अनदेखी पड़ेगी भारी

खुद को मुख्यमंत्री नहीं, योगी मॉडल के प्रतीक के रूप में किया स्थापित, जनप्रियता बनाम संगठनात्मक संतुलन के दो छोरों पर खड़ी है राजनीति

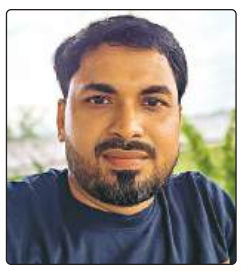

अनूप अवस्थी, स्वराज इंडिया

संगठनात्मक सामंजस्य के बीच संतुलन बनाना योगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हैं, जिनकी पहचान सख्त प्रशासक और निर्भीक निर्णयकर्ता की है। उनकी कार्यशैली न केवल राज्य की नौकरशाही को अनुशासित करने में सफल रही है, बल्कि भाजपा के भीतर भी एक अलग प्रशासनिक मॉडल के रूप में देखी जा रही है। हालांकि, यही कार्यशैली अब 2027 के राजनीतिक समीकरणों के केंद्र में है जहाँ लोकप्रियता और

2017 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने राज्य प्रशासन को ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुनर्गठित किया। अपराध नियंत्रण, माफिया पर कार्रवाई, अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र नीति और सरकारी तंत्र की जवाबदेही इन सबने जनता में एक नई उम्मीद जगाई। उनकी छवि एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय नेता की बनी, जिसने जनता में भय के बजाय विश्वास पैदा किया कि शासन सक्रिय है।

राजनीतिक तौर पर, योगी ने खुद को सिर्फ एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि योगी मॉडल के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। यह मॉडल प्रशासन पहले, राजनीति बाद में की सोच पर आधारित है जो पारंपरिक भाजपा शैली से कुछ अलग है, जहां संगठन और सरकार समानांतर रूप से चलते हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति इस समय जनप्रियता बनाम संगठनात्मक संतुलन के दो छोरों पर खड़ी है। वे जनता में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, पर भाजपा संगठन के भीतर उनके प्रति मिश्रित भावनाएं हैं।

2027 का चुनाव यह तय करेगा कि योगी आदित्यनाथ अपनी सख्त प्रशासक की पहचान को सर्वस्वीकार्य राष्ट्रीय नेता के रूप में कितना आगे बढ़ा पाते हैं। अभी के लिए इतना निश्चित है योगी न सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग का नाम हैं, जो भारतीय राजनीति की दिशा और परिभाषा दोनों को बदल रहा है।

निर्णयों में आत्मनिर्भरता, संगठन में दिखती असहजता

सीएम योगी की कार्यशैली का सबसे बड़ा पहलू है उनकी पूर्ण स्वायत्तता। वे अधिकांश निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से ही करते हैं। यह प्रणाली प्रशासनिक दृष्टि से प्रभावी साबित हुई, पर इससे भाजपा संगठन के भीतर असहजता भी बढ़ी। कई विधायक और पदाधिकारी शिकायत करते हैं कि जिला स्तर पर उनकी कोई भूमिका नहीं बची। थानों, एसडीएम और डीएम तक अफसर सीधे मुख्यमंत्री की लाइन पर काम करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मॉडल शासन में पारदर्शिता तो लाया है, लेकिन राजनीतिक संवाद की परंपरा को कमजोर किया है। यही कारण है कि संगठन और सरकार के बीच एक मौन दूरी बनती जा रही है, जो 2027 में पार्टी के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है।

केंद्र से बढ़ती दूरी और राजनीतिक स्वतंत्रता

बीते कुछ महीनों में यह सवाल लगातार उभर रहा है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक शैली केंद्र की अपेक्षाओं से कितनी मेल खाती है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह सशक्त व्यक्तित्व के प्रतीक हैं–जो हर स्तर पर अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। पर भाजपा की पारंपरिक संरचना सामूहिक नेतृत्व पर टिकी है।

राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच संवाद में कुछ ठंडापन आया है। मुख्यमंत्री योगी का कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों से अलग रहना और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सीमित प्रशंसा–इन संकेतों ने चर्चाओं को और तेज किया है।

हालांकि, योगी का प्रशासनिक प्रदर्शन और जनता में उनकी लोकप्रियता अब भी मजबूत है। यही वजह है कि भाजपा नेतृत्व उनके प्रति सख्त रुख अपनाने के बजाय संतुलन की रणनीति पर काम कर रहा है।

2027 के विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होंगे। एक ओर उनके पास जनता का मजबूत समर्थन है, दूसरी ओर पार्टी संगठन में संवाद की कमी। यदि यह दूरी बनी रही, तो यह भाजपा की चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकती है। भाजपा के लिए योगी एक मजबूत चेहरा हैं, लेकिन पार्टी यह भी नहीं चाहती कि कोई मुख्यमंत्री राष्ट्रीय समानांतर शक्ति केंद्र बन जाए। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में योगी को शासन की सख्ती और संगठन के तालमेल दोनों में संतुलन साधना होगा।

'योगी मॉडल' की राष्ट्रीय चर्चा

योगी आदित्यनाथ अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नेता नहीं रहे। देश के कई राज्यों में भाजपा समर्थक वर्ग योगी मॉडल को शासन का आदर्श मानता है जहां अपराध पर नियंत्रण, धर्म-सांस्कृतिक गौरव और प्रशासनिक जवाबदेही तीनों समानांतर चलते हैं। हालाकि, यह मॉडल उतना ही जोखिम भरा भी है, क्योंकि यह पूरी तरह एक व्यक्ति की छवि पर निर्भर करता है।

यदि 2027 में योगी भाजपा को एक और ऐतिहासिक जीत दिलाने में सफल होते हैं, तो वे निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाएंगे। पर यदि संगठनात्मक दूरी या राजनीतिक विरोधाभास बढ़े, तो यही कार्यशैली उनके लिए चुनौती बन सकती है।

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने सीएफसी का किया निरीक्षण

नगर आयुक्त के औचक निरीक्षण से बढ़ेगी नागरिक सेवाओं की पारदर्शिता

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय (आई.ए.एस.) द्वारा आज प्रातः नगर निगम मुख्यालय स्थित सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर (CFC) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त, सीएफसी प्रभारी एवं आईटी एक्सपर्ट राहुल सब्बरवाल सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने नागरिकों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों, शिकायतों और आवेदनों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने शिकायत पंजीकरण की प्रक्रिया, ऑनलाइन सिस्टम की कार्यक्षमता और रिकॉर्ड संधारण की समीक्षा की।

श्री उपाध्याय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों एवं आवेदनों का पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है, इसलिए यहाँ आने वाले प्रत्येक नागरिक को शीघ्र और संतोषजनक सेवा मिलनी चाहिए।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब पाया गया तो संबंधित कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने नागरिक सुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए — जिनमें प्रतीक्षा कक्ष, बैठने की व्यवस्था, पेयजल सुविधा और सूचना डिस्प्ले बोर्ड को और सुदृढ़ बनाना शामिल है।

श्री उपाध्याय ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य नागरिकों को पारदर्शी, त्वरित और सुगम सेवाएं प्रदान करना है। हर अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों का अनुभव नगर निगम में सकारात्मक और सहज हो।

औचक निरीक्षण के इस कदम से नगर निगम की नागरिक केंद्रित कार्यशैली को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। नागरिकों ने भी नगर आयुक्त की इस सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि इससे शिकायत निस्तारण व्यवस्था और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनेगी।

केडीए ने बर्रा-5 स्थित परिसर को किया सील

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) द्वारा अवैध निर्माणों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 24 अक्टूबर 2025 को बड़ी कार्रवाई की गई।

उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्यांयाल के निर्देश एवं सचिव अभय पांडे के आदेश के अनुपालन में थाना बर्रा क्षेत्रान्तर्गत परिसर संख्या-108, बर्रा-5, कानपुर नगर को सील करने की कार्यवाही की गई।

यह कार्रवाई प्रभारी अधिकारी (प्रवर्तन जोन-3) के निर्देशन में, संबंधित प्रवर्तन के अवर अभियंता अटल चतुर्वेदी एवं अन्य स्टाफ की उपस्थिति में की गई। कानपुर विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माण कार्यों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेंगी। केडीए ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकरण से आवश्यक मैप स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें।

अस्पताल के पास प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नौबस्ता स्थित आवास विकास हंसपुरम में एक प्लास्टिक गोदाम के बाहर रखे कबाड़ में शुक्रवार शाम आग लग गई। दमकल की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर एक घंटे में आग पर काबू पाया। कानपुर में नौबस्ता थानाक्षेत्र के आवास विकास हंसपुरम में शुक्रवार शाम प्लास्टिक गोदाम में जमा कबाड़ के ढेर में आग लग गई। पास में एक अस्पताल होने के कारण लपटें देख आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने एक घंटे में आग पर काबू पा लिया।

पीड़ित सोनू दीक्षित ने बताया कि राजरानी हॉस्पिटल के पास किराए के प्लॉट में प्लास्टिक गोदाम बना रखा है। शुक्रवार देर शाम गोदाम के बाहर जमा कबाड़ के ढेर में आग लग गई। नौबस्ता इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। कोई जनहानि नहीं हुई है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था।

बीएनडी कॉलेज में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से साख पर 'बट्टा'

गंभीर आरोप की शिकायत पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने दिए जांच के आदेश

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर के प्रतिष्ठित बीएनडी महाविद्यालय में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विवेक द्विवेदी और प्रबंध समिति पर आरोप है कि उन्होंने नियुक्तियों में भारी वित्तीय अनियमितताएं कीं और बिना वैध अनुमोदन के नियुक्तियां कर डालीं। शिकायतों के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच के आदेश जारी किए हैं, जिससे अब कॉलेज प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

शिकायतकर्ता एवं निलंबित कर्मचारी शशांक शुक्ला ने अपने आरोपों में कहा है कि नवंबर-दिसंबर

» कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विवेक द्विवेदी और प्रबंध समिति पर आरोप है कि उन्होंने नियुक्तियों में भारी वित्तीय अनियमितताएं कीं और बिना वैध अनुमोदन के नियुक्तियां कर डालीं हैं

2024 में कॉलेज में कई पदों पर नियुक्तियां की गईं, जबकि उस समय प्रबंध समिति का अनुमोदन समाप्त हो चुका था।

इसके बावजूद नियुक्तियां जारी रहीं और बाद में फरवरी 2025 में समिति के नवीनीकरण का आवेदन कर इसे पूर्व प्रभाव से मान्यता दिला दी गई।

शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि इन नियुक्तियों के बदले 15 से 32 लाख रुपये तक की वसूली की गई।

इस आरोप के समर्थन में एक

स्वराज इंडिया

कानपुर सिटी

06

ब्रह्मानंद पीजी कॉलेज में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के आरोपों की होगी जांच

आडियो रिकार्डिंग भी दी गई है, जिसमें कथित तौर पर कॉलेज प्रशासन से जुड़े लोगों और कुछ अधिकारियों के बीच पैसों के लेनदेन की बातचीत दर्ज बताई जा रही है।

यदि यह रिकार्डिंग और अन्य साक्ष्य सही पाए जाते हैं, तो यह मामला उच्च शिक्षा संस्थानों में हो रहे भ्रष्टाचार और प्रबंधन की साठगांठ का एक बड़ा उदाहरण बन सकता है।

इस बीच, प्राचार्य डॉ. विवेक द्विवेदी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा, शशांक शुक्ला और उसके सहयोगी झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी जांच हो चुकी है, जिसमें कुछ साबित नहीं हुआ। शासन से जो भी जांच होगी, उसमें पूरा सहयोग करेंगे।

अब सभी की निगाहें इस जांच पर टिकी हैं, जिससे बीएनडी कॉलेज ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य निजी और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

वही कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विवेक द्विवेदी का कहना है कि साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं इनकी जांच हो जाएगी सब क्लियर हो जाएगा।

सेंट्रल को विश्वस्तरीय स्वरूप देने के लिए कदम हुए तेज

जीएम नरेश पाल सिंह ने किया निरीक्षण यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं

» मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर चल रहे विकास एवं पुनर्विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन की गहन समीक्षा की। महाप्रबंधक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि यात्रियों को शीघ्र ही बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिल सकें।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, रनिंग रूम और स्टेशन परिसर की स्वच्छता व्यवस्था का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जीएम ने चलती ट्रेन से ट्रैक और सिग्नल की विंडो ट्रेलिंग जांच की और कहा कि कानपुर स्टेशन का पुनर्विकास कार्य संतोषजनक प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के बाद स्टेशन को विश्वस्तरीय स्वरूप मिलेगा। जीएम ने बताया कि छठ पर्व पर 210 विशेष गाडियां चलाई जा रही हैं। जिसमें कानपुर सेंट्रल से 40 और गोविंदपुरी से 24 ट्रेनें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। महाप्रबंधक ने बताया कि स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है।

आरपीएफ और जीआरपी की टीमें भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए सिटी साइड और कैंट साइड दोनों ओर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। जिससे प्लेटफॉर्म पर नियंत्रित संख्या में ही यात्री प्रवेश कर सकें। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना है।

निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक, सीटीएम आशुतोष सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जीएम को चल रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति रिपोर्ट भी सौंपी। इससे पहले महाप्रबंधक ने फतेहपुर स्टेशन का भी निरीक्षण किया।

ऑपरेशन कन्विक्शन में जीआरपी भीमसेन ने दिलाई दो अभियुक्तों को सजा

» मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत जीआरपी भीमसेन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना जीआरपी भीमसेन पुलिस टीम ने प्रभावी विवेचना और पैरवी करते हुए दो अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाई है।

पुलिस अधीक्षक रेलवे झांसी विपुल कुमार श्रीवास्तव एवं पुलिस उपाधीक्षक रेलवे झांसी सोहराब आलम के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष हेमन्त कुमार सोलंकी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के तहत अभियुक्त अंकित कुमार एवं ललित कुमार गौतम, दोनों निवासी राम सिंह का पुरवा, थाना सचेण्डी, कानपुर नगर को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध पाया गया।

एसीजेएम रेलवे कोर्ट बांदा ने दोनों अभियुक्तों को जेल में व्यतीत अवधि तथा 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 5 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। थानाध्यक्ष हेमन्त कुमार सोलंकी ने बताया कि इस तरह की सजा से अपराधियों में भय और कानून के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अन्य लंबित मामलों में भी प्रभावी पैरवी कर दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी, जिससे समाज में शांति और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।

छठ से पहले घाटों की बदहाली, नमामि गंगे के दावे धराशायी

लोग बोले– अधिकारी सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं, असली सफाई नहीं होती, छठ पर्व पर श्रद्धालु परेशान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। छठ पूजा और कार्तिक मास के मौके पर गंगा घाटों की हालत न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुँचा रही है। नानामऊ, अकबरपुर सेंग, आकिन और सरैया घाटों पर प्लास्टिक, टूटी मूर्तियाँ और अन्य कचरा फैला हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई कर्मचारी केवल फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं और वास्तविक सफाई का काम नहीं होता।

स्थानीय निवासी विनय उपाध्याय ने कहा,छठ पूजा जैसे पर्वों में हजारों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन घाटों की इस स्थिति ने हमारी उम्मीदों और श्रद्धालुओं की आस्था पर गंभीर चोट पहुंचाई है। नानामऊ घाट पर प्लास्टिक, पॉलीथिन और टूटे मूर्तियों के अवशेष तट पर बिखरे पड़े हैं। बिल्हौर के अन्य घाट अकबरपुर सेंग, आकिन और सरैया की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। घाटों पर बने शौचालय और पेयजल की व्यवस्था बंद या गंदगी से भरी पड़ी है। श्रद्धालुओं को न स्नान के लिए स्वच्छ जल मिल पा रहा है और न पूजा के लिए साफ जगह।

स्थानीय लोगों का कहना है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत हर साल लाखों रुपये घाटों की सफाई के लिए जारी होते हैं, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता। अनुरुद्ध ने कहा, अगर प्रशासन समय रहते घाटों की सफाई नहीं करता, तो श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत घाटों की सफाई, जल गुणवत्ता सुधार और रखरखाव के दावे किए जाते हैं, लेकिन बिल्हौर के घाटों की वर्तमान स्थिति योजना की विफलता को स्पष्ट रूप से दिखाती है। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, लेकिन घाटों की अस्वच्छ स्थिति इस धार्मिक अनुष्ठान की पवित्रता पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है। स्थानीय लोगों ने घाटों पर सफाई की मांग की है।

बहू को बाल पकड़कर घसीट-घसीट कर पीटा

सास-बहू का विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। रहीमपुर विषधन गांव में मामूली घरेलू कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। सास ने अपनी बेटियों को बुलाया, जिन्होंने बहू को बेरहमी से पीटा। पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत किया। बिल्हौर सर्किल के ककवन थाना क्षेत्र के रहीमपुर विषधन गांव में घरेलू विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया।

पीड़ित बहू नीतू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 22 अक्टूबर को उनकी सास ने अपनी बेटियों रेखा पाल (कानपुर देहात बारापुर) और रीना (खमैला, कानपुर देहात) को घर बुलाया। दोनों बहनें घर पहुंचीं और नीतू को बाल पकड़कर घसीटते हुए लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। इस दौरान नीतू के हाथ में गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर मामले को शांत किया। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई, जिसने आरोपियों की बेरहमी सबके सामने उजागर कर दी। नीतू ने पुलिस को बताया कि आरोपी पहले भी कई बार उसके साथ मारपीट कर चुके हैं। ननद-ननदोई अक्सर उसे जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। उनके पति बाहर नौकरी करते हैं और नीतू अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हैं।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण इस घटना पर चर्चा कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या अकेली महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून पर्याप्त है।

गाय-भैंस चोर बताकर ग्रामीणों ने वनकर्मियों को लात-घूंसों से पीटा!

कछुए का मांस पकाने की सूचना पर दुर्गापुर गांव पहुँची टीम पर हमला

» **मोबाइल-पर्स छीने, कमरे में बंद करने की कोशिश।**

» **वन दरोगा की तहरीर पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज।**

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर(कानपुर)। प्रतिबंधित कछुए का मांस पकाने की सूचना पर कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम खुद पिट गई। दुर्गापुर गांव में नशे में धुत कुछ लोगों ने वनकर्मियों को घेरकर लात-घूंसों से पीटा और उनका मोबाइल व पर्स छीन लिया। जानकारी के मुताबिक शिवराजपुर थाना क्षेत्र के हरिराय नेवादा पंचायत के दुर्गापुर गांव में 21 अक्टूबर को हुई घटना ने वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सूचना मिली थी कि कुछ लोग कछुए का शिकार कर उसका मांस पका रहे हैं। वन विभाग के संविदा कर्मी रिंकू, कल्लू और आशीष सूचना पर मौके पर पहुँचे। जब उन्होंने मांस जब्त करने का प्रयास किया, तो दावत उड़ाते ग्रामीण बेकाबू हो गए। उन्होंने वनकर्मियों को गाय-भैंस चोर कहकर लात-घूंसों से मारपीट की। घटना के दौरान कुछ गांव वालों ने भी हमले में हाथ साफ किया।

ग्रामीणों ने वनकर्मियों को कमरे में बंद करने की कोशिश भी की। इस हमले में एक कर्मी को गंभीर चोटें आईं, जबकि एक का मोबाइल और पर्स छीना गया। घटना स्थल से कुछ दूरी पर मौजूद वन दरोगा अमित कटियार ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुँचने से पहले हमलावर फरार हो गए। वन दरोगा ने बताया कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुँचती, तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सभी हमलावर नशे की हालत में थे।

शिवराजपुर इंस्पेक्टर वरुण कुमार शर्मा ने वन दरोगा की तहरीर पर तीन नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

सम्पादकीय

अमेरिका-रूस में संतुलन साधने की चुनौती

सत्ता में आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप भारत पर चारों तरफ से जिस तरह से दबाव बनाते रहे हैं, उसके निहितार्थ समझना कठिन नहीं है। एक ही मुद्दे पर उनकी नीति चीन-पाकिस्तान व भारत को लेकर अलग-अलग होती है। उनके हालिया कदमों से भारतीय विदेश नीति असहजता के दौर से गुजर रही है। ट्रंप की भारत को मुश्किल में डालने की तमाम घोषणाएं, अब चाहे मनमाना टैरिफ थोपना हो या भारतीय प्रतिभाओं व नागरिकों पर तरह-तरह की बंदिशे लगाना हो, भारतीय जनमानस में नाराजगी का सबब बनती रही हैं। जानकार मानते हैं कि ट्रंप ये दबाव अमेरिका की प्राथमिकताओं के साथ व्यापार समझौते पर भारत को झुकाने के लिये बना रहे हैं। अब इसी कड़ी में रूस से आने वाला सस्ता तेल बंद करवाना ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता बनी है। भारत कहता रहा है कि वह अपने 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों को अपने बजट में लाने हेतु रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिसका रूस-यूक्रेन युद्ध से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन भारत की सॉफ्ट विदेश नीति पर दबाव बनाने हेतु ट्रंप प्रशासन कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी कड़ी में रूसी तेल के दो सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं रोसनेफ्ट और लुकोइल, पर अमेरिकी कड़े प्रतिबंध भारत को की जाने वाली रूसी तेल की आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं। संभव है कि भारत के क्रूड ऑयल खरीदने के विकल्प इन प्रतिबंधों से सीमित हो सकते हैं। कुछ राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि यह कदम अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते में एक बड़ी बाधा दूर करने वाला कारक भी साबित हो सकता है। कुछ जानकार राष्ट्रपति ट्रंप की यह घोषणा, रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिये रुकी हुई वार्ताओं को लेकर बढ़ती निराशा से उपजी बता रहे हैं।यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में मास्को द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद, भारत रियायती रूसी कच्चे तेल का दूसरा बड़ा खरीददार रहा है। वहीं दूसरी ओर वाशिंगटन प्रशासन का आरोप रहा है कि तेल कंपनियां क्रेमलिन की युद्ध मशीन को वित्तपोषित करने में मदद कर रही हैं। ट्रंप और उनके टीम के सदस्य कई बार भारत पर रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के बेतुके आरोप भी लगाते रहे हैं। जिसके चलते ट्रंप प्रशासन ने रूसी कच्चे तेल का आयात करने पर प्रतिशोध के चलते भारत से आने वाले सामानों पर 25 फीसदी का दंडात्मक शुल्क भी लगाया था।

भारत सरकार के लिये यह श्रेय की बात है कि वह रूसी तेल खरीद रोकने के दबाव का दृढ़ता से विरोध करती रही है। भारत सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। निस्संदेह, भारत को अब एक और कठिन संतुलन साधने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौजूदा चुनौतियों के बीच यदि एक सुनियोजित पुनर्निधारण की आवश्यकता है, तो ऐसा करना चाहिए। वैसे भारी दबाव के बाद भी मोदी सरकार ने ट्रंप सरकार के बार-बार दिए गए उस बयान से खुद को अलग कर लिया है कि वह रूसी तेल आयात में भारी कमी लाएगी। लेकिन अब नये प्रतिबंधों का पालन करने के लिये भारतीय रिफाइनरियों के लिये अल्पावधि में रूसी तेल सौदों से पीछे हटना निश्चित प्रतीत होने लगा है। आने वाले समय में यह दबाव कितना रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप, दोनों इस नवीनतम टकराव को किस हद तक झेलने के लिये तैयार हैं। भारतीय रिफाइनरियां आवश्यकता पड़ने पर आसानी से नये स्रोतों की ओर रुख कर सकती हैं और अमेरिकी टैरिफ में कमी करके महंगे तेल आयात की भरपाई की जा सकती है। भारत के हितों के अनुकूल निर्णय लेने की अपनी स्वायत्तता पर जोर देना, नई दिल्ली के लिये असली चुनौती है।

दवा उद्योग नहीं, जन स्वास्थ्य को मिले प्राथमिकता

ज्योति निरंजन

मानदंड तो मौजूद हैं, उन्हें और अधिक कठोर बनाने के लिए संशोधित भी किया जाता है, लेकिन उन्हें लागू करने की कोई इच्छाशक्ति नहीं है। केंद्रीय और राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण, जिनके जिम्मे मानदंड लागू करवाने का काम है, कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं या जानबूझकर कर्मचारियों की कमी बना रखी है। ज़हरीले औद्योगिक रसायन की मौजूदगी वाले कफ़ सिरप के सेवन से काफी तादाद में हुई बच्चों की मौतें भारत की नाकाम दवा नियंत्रण एवं नियामक प्रणाणी पर फिर से ध्यान खींचती हैं। हाल के वर्षों में, स्वदेश और विदेशों में भी, भारत निर्मित दवाओं से जुड़ी ऐसी कई दुखद घटनाएं हुई हैं।

हर बार, हमारी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है— मौतों का ज़िम्मेदार विषाक्त या घटिया दवाओं को ठहराया जाता है, राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जांच की रस्म निभाई जाती है, कुछ छिटपुट उत्पादन इकाइयों पर छापे मारे जाते हैं, नियमों का सही ढंग से पालन न करने की रिपोर्ट आती है, कुछेक इकाइयों के उत्पाद लाइसेंस निलंबित कर दिए जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को नियामक मानदंडों को 'सख्ती से' लागू करवाने का निर्देश दिया जाता है। फिर जल्द ही 'पहले जैसा क्रियाकलाप' शुरू हो जाता है। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, नियम जस-के-तस, दवा नियामक निकायों में रिक्त पदों को नहीं भरा जाता, किसी भी दोषी इकाई को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जाता, और पिछली घटनाओं की जांच के निष्कर्षों को साझा करने की कोई ज़हमत नहीं उठाता। कफ़ सिरप को जहरीला बनाने वाले कारक अब सर्वविदित हैं - डाईइथालिन ग्लाइकॉल और इथाईलिन ग्लाइकॉल। इन दोनों जहरीले रसायनों के विषाक्त प्रभावों में पेटदर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब करने में असमर्थता, सिरदर्द, मानसिक स्थिति में बदलाव और गुर्दे को गंभीर आघात शामिल हैं, जिससे मौत भी हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कफ़ सिरप बनाते समय, खासकर प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जैसे घटकों का उपयोग करने वाले सिरपों में, डाईइथालिन ग्लाइकॉल और इथाईलिन ग्लाइकॉलर रसायनों का उपयोग मिलते जुलते नामों में गफलत होने से हो जाता है। गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून, इराक और अन्य देशों में 'भारत में निर्मित' उत्पादों के सेवन से दर्जनों बच्चों की मौत के बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वहां के राष्ट्रीय नियामकों और स्वास्थ्य अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनके देशों में ऐसे उत्पाद पाए जाते हैं, तो उसकी सूचना दें। एजेंसी ने राष्ट्रीय अधिकारियों को दवाओं के उपयोग से पहले उनकी उत्पादन सामग्री में डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल की उपस्थिति की जांच करने की सलाह दी है। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई मौतों के लिए भी यही डाईइथाइलिन ग्लाईकॉल ज़िम्मेदार है।ज होता है कि कफ़ सिरप निर्माता इतने लापरवाह हैं कि उनके उत्पाद की सामग्री में घातक विषाक्त पदार्थ का उपयोग हो जाए। निःसंदेह, वे अनिवार्य शर्त यानी 'गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज' (जीएमपी) नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब या तो वे जीएमपी का पालन नहीं कर रहे या सरकार ने उन्हें लंबी रस्सी दे रखी है जहरीली दवाओं से होने वाली हर मौत के बाद, जीएमपी लागू करने या उसे और सख्त बनाने की बात होती है। लेकिन जैसे ही अमल होने लगता है, लघु एवं मध्यम दवा निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग संघ जीएमपी नियमों को लागू करने के लिए समय मांगते हैं या उनमें ढील देने की मांग करते हैं, यह बहाना बनाते हैं कि उनके पास मानदंडों को लागू करने लायक क्षमता नहीं है।

प्रकृति व आध्यात्मिक चेतना के प्रति जिम्मेदारी समझें

प्राकृतिक आपदाएं

ज्वाला सिंह दास

प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता से भरपूर तीर्थ स्थलों के हृदय क्षेत्र में सड़क, रोपवे और रिजोर्ट्स का निर्माण उचित नहीं है। प्रकृति की गोद में स्थित इन स्थलों का आदर्श एकांत और साधना का वातावरण रहा है, जहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा श्रम करना तप के रूप में माना जाता था। हिमालय आज रुष्ट प्रतीत हो रहा है और अपनी विप्लवी हलचलों के माध्यम से मानवता को चेतावनी दे रहा है। इंसान ने हिमालय के साथ जो खिलवाड़ किया है, वह चिंताजनक और क्षोभ उत्पन्न करने वाला है।

महत्वाकांक्षाएं प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं, जो प्रकृति के प्रति न्यूनतम संवेदना की कमी को दर्शाती हैं।वर्ष 2025 में प्रकृति ने हिमालय के हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर प्रांतों में विनाशकारी तांडव किया, जिसके भयावह परिणाम पंजाब और दिल्ली तक देखने को मिले और इसका असर प्रयागराज से बनारस यह घटना हिमालय की चेतावनी को ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक मौसम परिवर्तन जैसी घटनाओं में भले ही प्रभावित लोगों का सीधा हाथ न हो, लेकिन इनका नाम लेकर हम अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। अपनी बेवकूफियों और अदूरदर्शिता को छुपाना या प्रकृति-विरोधी योजनाओं को विकास का रूप देना अब नहीं चल सकता। इस प्राकृतिक आपदा में जिनकी जान गई, उनकी आत्माओं के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए और उनके परिजनों के प्रति हार्दिक सांत्वना जाहिर की जाती है। सभी से यह निवेदन किया जाता है कि प्रकृति के

प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें ा, जो अपनी संतानों की रक्षा और पोषण करती है। हमें इस मां के प्रति कृतज्ञता और सम्मान के साथ काम करना चाहिए, ताकि उसकी कृपा हम पर बनी रहे। अगर हम प्रकृति को भोग्य वस्तु मानकर उसका अत्यधिक शोषण करते हैं, तो इसके नतीजे को भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा। वर्ष 2025 में हिमालय क्षेत्र में शिव-शक्ति से जुड़े तीर्थस्थलों के आसपास प्राकृतिक आपदाएं अधिक आई हैं,

जो एक स्पष्ट संकेत हैं कि प्रकृति रुष्ट है। प्रकृति की अधिष्ठात्री मां जगदम्बा और भगवान शिव रुष्ट हैं, और महाकाल-महाकाली अपना ताण्डव नृत्य करने के लिए विवश हो गए हैं। वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक विध्वंस करने के लिए बाध्य हैं, जो हमें प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का संदेश देता है। वर्तमान में तीर्थ स्थलों को मानव ने पिकनिक स्पॉट और व्यापारिक केंद्र बना दिया है, जहां तीर्थयात्रियों को लूटने का कारोबार होता है, जो तीर्थ की गरिमा के अनुरूप नहीं है। बिना जीवन के सच्चे तप, सुधार और पात्रता के, मुफ्त में भगवान की कृपा की उम्मीद करना और तीर्थ स्थलों में गंदगी फैलाना, यह पूरी तरह से समझदारी के खिलाफ है। जो जीवन के मूल्यों की न्यूनतम समझ का भी अभाव दर्शाता है।ै, जो ईमानदारी, जिम्मेदारी और समझदारी पर आधारित होती है। गैरजिम्मेदार आचरण, बेईमानी और अहंकार से इसका कोई संबंध नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता से भरपूर तीर्थ स्थलों के हृदय क्षेत्र में सड़क, रोपवे और रिजोर्ट्स का निर्माण उचित नहीं है। प्रकृति की गोद में स्थित इन स्थलों का आदर्श एकांत और साधना का वातावरण रहा है, जहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा श्रम करना तप के रूप में माना जाता था। जो लोग अशक्त हैं, उनके लिए कंडी और अन्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जो स्थानीय लोगों के रोजगार का भी कारण बनती हैं। इस तरह की अव्यवस्थित विकास योजनाओं से इन स्थानों की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। वर्ष 2025 के प्रकृति तांडव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नदियों और जल स्रोतों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, और इन्हें हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए।

मां का प्रेमी निकला 6 साल के मासूम का कातिल, पुलिस मुठभेड़ में घायल

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बर्रा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर में छह साल के मासूम आयुष सोनकर का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बच्चे की मां के प्रेमी शिवम सक्सेना (22) पर है, जिसने मासूम को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया और बाद में उसका गला दबाकर कत्ल कर शव पांडु नदी किनारे फेंक दिया। देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में हत्यारोपी को दबोच लिया।

» चॉकलेट का लालच देकर बच्चे को घर से ले गया पड़ोसी शिवम सक्सेना

» पांडु नदी किनारे मिला था मासूम का शव, पुलिस कार्रवाई में घायल हत्यारोपी

पुलिस के मुताबिक घटना के बाद घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जिसमें शिवम बच्चे को अपने साथ ले जाते और बाद में अकेले लौटते हुए दिखा। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि फुटेज के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया और नदी किनारे से बच्चे का शव बरामद हुआ।

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि शिवम और आयुष की मां ममता के बीच प्रेम संबंध थे, जिससे दोनों परिवारों में पहले से विवाद चल रहा था। ममता के पति माखन सोनकर राजमिस्त्री हैं और दोनों परिवार एक ही मकान में किराए पर रहते थे। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन देर रात पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने उसका पीछा किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। डीसीपी साउथ ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। इस वारदात ने शहर में गुस्सा और गम दोनों को जन्म दिया है। स्थानीय लोग आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।

मृत बच्चे की फाइल फोटो

मुरादाबाद: सातवीं की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने वाला मदरसा इंचार्ज गिरफ्तार

» मुरादाबाद की घटना ने झकझोरा समाज को — जब 7वीं की छात्रा से मांगा गया वर्जिनिटी सर्टिफिकेट

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक शर्मनाक और विचलित करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मदरसे ने 7वीं कक्षा की छात्रा से गाइनकोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रमाणित वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाने की मांग की। ऐसा न करने पर छात्रा का नाम मदरसे से काट देने की धमकी दी गई। पीड़ित बच्ची के पिता ने जब इस अमानवीय मांग का विरोध किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो मामला सार्वजनिक हुआ।पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मदरसे के एडमिशन सेल इंचार्ज शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मदरसा प्रिंसिपल रहनुमा की तलाश में टीमें गठित की गई हैं।

यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समाज की बीमार मानसिकता और महिलाओं के प्रति अविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण का आईना भी है। सवाल यह उठता है कि आखिर एक शिक्षण संस्था — जो नैतिकता, ज्ञान और आस्था की जगह होनी चाहिए — वहां ऐसी अमानवीय सोच कैसे पनप गई ?एक नाबालिग बच्ची से पवित्रता का प्रमाण मांगना न सिर्फ संवैधानिक मूल्यों का अपमान है बल्कि यह महिला सम्मान और बचपन की गरिमा पर भी आघात है।

सामाजिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में व्याप्त महिलाओं को वस्तु समझने की मानसिकता का नतीजा हैं। जब किसी बच्ची की मासूमियत पर शक किया जाता है, तो यह पूरे समाज की सोच पर सवाल खड़ा करता है ऐसी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि शिक्षा के मंदिरों में अगर संकीर्ण सोच और पितृसत्तात्मक मानसिकता की जड़ें जम जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों में हम कौन से संस्कार बो रहे हैं?

सरकार की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, परंतु जरूरत इस बात की है कि समाज के हर वर्ग में लैंगिक संवेदनशीलता और सम्मान की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक कानून भी सीमित ही रह जाएंगे।

सीएम योगी के प्रयासों से पुनः शुरू हुई संभल की पौराणिक 24 कोसी परिक्रमा

» 46 वर्षों बाद लौट रहा संभल अपने आध्यात्मिक स्वरूप में, सांस्कृतिक धरोहर को मिल रही नई पहचान

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ।यूपी का संभल एक बार फिर अपने प्राचीन आध्यात्मिक वैभव को पुनः प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को नया जीवन मिल रहा है। शुक्रवार की मध्यरात्रि 2 बजे संभल की 24 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ प्राचीन बेनीपुरचक स्थित श्रीवंशगोपाल तीर्थ से हुआ। शंखनाद, भजन और जयघोषों के बीच लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने।

यह परिक्रमा 46 वर्षों बाद पुनः प्रारंभ हुई है। वर्ष 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद यह परंपरा थम गई थी, लेकिन अब योगी सरकार के प्रयासों से यह धार्मिक विरासत पुनर्जीवित हो उठी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस परिक्रमा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

वंशगोपाल तीर्थ से प्रारंभ होकर यह परिक्रमा भुवनेश्वर, क्षेमनाथ और चंदेश्वर तीर्थों से होते हुए पुनः वंशगोपाल तीर्थ पर समाप्त होती है। मार्ग में 87 देवतीर्थ स्थित हैं, जो सम्भल की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक हैं।

2017 के बाद संभल का बदला परिदृश्य

1978 के दंगों ने सम्भल की सामाजिक संरचना को गहरी चोट पहुंचाई थी। भय, अविश्वास और पलायन का दौर वर्षों तक यहां कायम रहा। अनेक मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जे हो गए थे, और धार्मिक आयोजनों पर रोक जैसी स्थिति बन गई थी। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। मुख्यमंत्री ने संभल के हालात पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लिया। न्यायिक आयोग की रिपोर्टों के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई और अवैध कब्जों को हटाया गया।

अवैध कब्जों से मुक्ति और धार्मिक धरोहरों का पुनरुद्धार

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए संभल में 495 वाद दर्ज किए, जिनमें से 243 मामलों का निस्तारण कर 1067 अतिक्रमण हटाए गए। इस कार्रवाई में 68.94 हेक्टेयर भूमि कब्जामुक्त कराई गई।

इसी तरह धार्मिक स्थलों पर हुए 37 अवैध कब्जे भी हटाए गए, जिनमें 16 मस्जिदें, 12 मजारें, 7 कब्रिस्तान और 2 मदरसे शामिल थे। कुल 2.623 हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराया गया। साथ ही 68 पौराणिक तीर्थस्थलों और 19 प्राचीन कूपों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। कल्कि अवतार मंदिर सहित कई स्थलों पर पुनरुद्धार का काम चल रहा है।

कुमारगंज के सौ शैय्या अस्पताल में खाली बेडों का 'साम्राज्य'

» 100 बेड के अस्पताल में सिर्फ दो मरीज और डॉक्टरों कर रहे नींद पूरी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।यह अयोध्या का एक सरकारी 100 बेड वाला चिकित्सालय है कागज़ों में 'सेवा का मंदिर', लेकिन हक़ीकत में 'आरामगाह'। महीने भर का हिसाब उठाइए बेड उपयोगिता 39 फीसदी, यानी 100 में सिर्फ 39 बेड भरे, बाकी 61 पर सन्नाटा। मेजर सर्जरी जीरो, आयुष्मान योजना के केस लगभग जीरो। स्टेमी केस नाम मात्र। कहते हैं, जब अस्पताल में मरीज कम हों तो डॉक्टर को चिंता होनी चाहिए, लेकिन यहां तो वेतन पर बहस है वेतन रोक दिया जाए या नहीं! किसी अधिकारी ने सही कहा, जब काम जीरो, तो सैलरी हीरो क्यों?

स्वराज इंडिया के विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएमएस डॉ रवि पांडेय ने कहा है कि माह अक्टूबर का वेतन आहरण रद्द कर सूचना महानिदेशक स्वास्थ्य एवं अपर निदेशक अयोध्या मंडल व जिलाधिकारी को भेज दी जाए। कारण यह बताया जा रहा है कि 100 बेड के अस्पताल में केवल दो भर्ती मरीज। मेजर सर्जरी का आंकड़ा शून्य। ओपीडी 400-500 और इमरजेंसी 20-25 प्रतिदिन, लेकिन नतीजा वही काम कम, बहाने ज्यादा। सरकारी अस्पतालों में यह नई प्रवृत्ति है आंकड़े भले गिर रहे हों, लेकिन चेहरों पर शिकन नहीं। आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना यहां के चिकित्सकों के लिए बोझ बन गई है, जबकि गरीब मरीज इसके भरोसे ही सरकारी दहलीज़ पर आता है। लेकिन जब मरीज पहुंचता है, तो कभी डॉक्टर 'मीटिंग में', कभी 'राउंड पर', कभी 'लंच पर'। इस बाबत प्रशासन की आंखें भी बंद हैं। जिला अस्पतालों की हालत का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि 39 प्रतिशत बेड उपयोगिता पर भी किसी की जवाबदेही तय नहीं। अब सवाल उठता है क्या वाकई वेतन रोकना ही एकमात्र रास्ता है, या पूरे सिस्टम की सर्जरी की ज़रूरत है?

स्वराज इंडिया के कुछ सवाल

जब सर्जरी जीरो, तो सर्जन किस काम में व्यस्त हैं?
जब आयुष्मान केस नहीं, तो गरीब कहां जा रहे हैं?
जब 100 बेड में 98 खाली हैं, तो सुविधाओं का क्या उपयोग?
जब मरीज कम हैं, तो मेडिकल रिकॉर्ड इतने फुल क्यों हैं?

घर के बाहर सो रही चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म

» रात में दादी के पास लेटी थी मासूम, भोर में खून से लथपथ मिली

एसीपी मौके पर पहुंचे, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार देर रात चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना से सनसनी फैल गई। मासूम घर के बाहर दादी के साथ चारपाई पर सोई थी। भोर करीब तीन बजे वह घर के बाहर ही बने शौचालय में अचेत अवस्था में रक्तरंजित हालत में मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

परिजनों के मुताबिक बच्ची की मां व पिता किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर दादी और अन्य परिजन मौजूद थे। रात में सभी लोग सो रहे थे। तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने मासूम के साथ हैवानियत की। जब परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो घर में हडक़ंप मच गया। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर एसीपी कृष्णकांत यादव और इंस्पेक्टर धनंजय कुमार पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी साक्ष्य संकलन के लिए बुलाया गया। बच्ची को घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। एसीपी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बच्ची का फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

बिकरू कांड से जुड़ी दो लग्जरी कारों पर नहीं लगी बोली

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कुख्यात बिकरू कांड से जुड़ी तीन लावारिस कारों में से एक कार की नीलामी हो गई, जबकि दो लग्जरी गाडिय़ों की ऊंची कीमत के कारण कोई खरीदार आगे नहीं आया। नीलामी काकादेव थाने में कोर्ट के आदेश पर कराई गई।

» आगरा के व्यापारी ने 22.40 लाख में खरीदे 75 वाहन, बिकरू कांड की कार 3.54 लाख में बिकी

» फॉर्चुयूनर और ऑडी की तय कीमत सुनकर पीछे हटे खरीदार, थाने में नहीं जुटा कोई दावेदार

जानकारी के अनुसार, दो जुलाई 2020 की रात चौबेपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। वारदात के दो दिन बाद पुलिस ने विजयनगर इलाके से तीन लावारिस कारें बरामद की थीं।

जांच में पता चला कि इन गाडियों का उपयोग विकास दुबे के करीबी जय बाजपेई करता था। गाडियां प्रमोद विश्वकर्मा, कपिल सिंह और राहुल सिंह के नाम पर पंजीकृत थीं, पर बीते पांच वर्षों में किसी ने भी मालिकाना दावा नहीं किया।शुक्रवार को हुई नीलामी में आगरा के व्यापारी धर्म सिंह ने बिकरू कांड से जुड़ी वरना कार को 3.54 लाख रुपये में खरीदा। उन्होंने अन्य चार, तीन और दोपहिया वाहनों सहित कुल 75 वाहन 22.40 लाख रुपये में खरीदे। वहीं, आरटीओ द्वारा निर्धारित कीमत के अनुसार ऑडी की कीमत 12 लाख और फॉर्च्यूनर की नौ लाख रुपये रखी गई थी, जिसे सुनकर किसी ने बोली नहीं लगाई। थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि बिकरू कांड से जुड़ी दो अन्य कारों की नीलामी अगली प्रक्रिया में की जाएगी।

लापरवाही या डेटा में हेरफेर कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी

ओटीडी सेल की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में जिला स्तरीय ओटीडी (वन ट्रिलियन डॉलर) सेल की बैठक की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिले के आर्थिक विकास से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में हुई प्रगति, उत्पादन, निवेश और रोजगार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने बताया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन तथा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त आधार मिला है। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन, निर्माण कार्यों, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर प्रगति हुई है, जबकि व्यापार, परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएं एवं पर्यटन के क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी कपिल सिंह ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए आर्थिक आंकड़ों में पाई गई विसंगतियों पर कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास रिपोर्ट सरकार की नीति निर्धारण प्रक्रिया की आधारशिला होती है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी बैठक में अधिकारी स्वयं उपस्थित रहें, अपने अधीनस्थों को न भेजें। उन्होंने तीन कार्यदिवसों के भीतर सभी विभागों को अपने आंकड़ों की पुन- समीक्षा कर संशोधित एवं प्रमाणिक डेटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में संशोधित रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

जिलाधिकारी ने उपायुक्त राज्य कर एवं सहायक निरीक्षक कारखाना की बैठक में अनुपस्थिति और उनके विभागीय आंकड़ों में पाई गई विसंगति को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह शासन के कार्यों में शिथिलता का द्योतक है। उन्होंने निर्देशित किया कि इन अधिकारियों के विरुद्ध शासन को प्रतिकूल टिप्पणी सहित पत्र भेजा जाए, ताकि ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि आंकड़ों का संकलन और सत्यापन पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए तथा रिपोर्ट के प्रत्येक बिंदु की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिले के विकास की गति तभी तेज होगी जब प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाए। लापरवाही या डेटा में हेरफेर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उपायुक्त कृषि, पंचायती राज विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अंत में सभी अधिकारियों से कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि कानपुर देहात आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और अग्रणी जिले के रूप में उभरे, जिसके लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा।

किसान यूनियन के कार्यकर्ता ने फांसी लगाकर दी जान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के ररूआ गांव में शुक्रवार देर रात 25 वर्षीय सूरज ने गांव के बाहर नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने देर रात पुलिस को दी। सूरज किसान यूनियन का कार्यकर्ता था।

गजनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि सुरज भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा था और संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता था। परिजनों का कहना है कि सुरज शशांत और मिलनसार स्वभाव का था।

किसान यूनियन से जुड़े कार्यकर्ता और ग्रामीण सुरज के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

सीधा सवाल: सीडीओ मैडम समय से कब खुलेगे पंचायत भवन

पंचायत भवन पर लटक रहे ताले, कागजों में ही हो रहा संचालन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिला प्रशासन से लेकर ब्लॉक मुख्यालय के अफसर लागतार अफसरों के साथ बैठक कर गांव के ग्रामीण का हर समस्या का समाधान करने के बात करते हैं। सरकार ने लाखो रुपए खर्च कर गांव को पंचायत भवन का निमार्ण कार्य कराया लेकिन अफसरों के अनदेखी से ग्राम पंचायत पातेपुर में शनिवार को पंचायत भवन में ताला लटका मिला।

यह भी पता चला है कि जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते अधिकतर पंचायत भवन ताला बंदी का शिकार हो गए हैं। सहायक पंचायत इसमें बैठने नहीं आते है। कुछ पंचायत में पंचायत सहायक की अभी तक नियुक्ति भी नहीं की गई है जिसके चलते ग्रामीणों का प्राथमिक स्तर के अधिकांश समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उन्हें कोसों दूर तय कर ब्लॉक के चक्कर लगाना मजबूरी बन गई है। अकबरपुर ब्लॉक के पातेपुर गांव के लोगों ने नाम न छापने के शर्त पर गांव के लोगों ने बताया है कि पंचायत भवन पर हमेशा ताला लटका रहता है

क्या बोले एडीओ पंचायत अकबरपुर

एडीओ पंचायत आदित्य शुक्ला का कहना है कि जानकारी मिली है पंचायत सचिव और संबंधित ग्राम प्रधान से जवाब तलब किया जायेगा और हर हाल में संचालन करवाया जायेगा।

पंचायत भवन पर ना तो विकास कार्यों को लेकर कभी बैठक की जाती है ना ही ग्रामीणों को प्राथमिक स्तर की सुविधा मिल पाती हैं। सबसे अहम बात की हाइवे किनारे बने पंचायत सचिवालय जबकि जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों का इसी हाइवे से आना जाना भी होता है फिर भी अफसरों के आंखों में धूल झोंकी जा रही है।

ट्रक पार्किंग के डिवाइडर पर उगी झाड़ियां दे रही हादसों को निमंत्रण

» कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अभी तक अनजान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद से कानपुर रोड पर विद्युत उपकेंद्र बिजली घर के पास सडक़ के किनारे बनी ट्रक पार्किंग के डिवाइडर पर उगी बड़ी बड़ी झाड़ियां अब स्थानीय लोगों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। इन झाड़ियों के कारण

सडक़ की दोनों दिशाओं से आने जाने वाले वाहनों की विज़िबिलिटी काफी कम हो गई है जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह झाडियाँ पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ती जा रही हैं लेकिन अब तक संबंधित विभाग की ओर से कोई सफाई या रखरखाव का कार्य नहीं किया गया है। ट्रक पार्किंग के पास भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में डिवाइडर पर उगी घनी झाडियों की वजह से ट्रक चालकों को सामने से आने वाले वाहनों का स्पष्ट अंदाजा नहीं हो पाता है। रात के समय यह समस्या और गंभीर हो जाती है क्योंकि झाडियों के बीच छिपे हुए संकेतक नजर नहीं आते हैं। राहगीरों ने बताया कि पहले भी यहां कई बार छोटे मोटे हादसे हो चुके हैं लेकिन अब स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है। लोगों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में नगर पंचायत और लोक निर्माण विभाग को शिकायत भी की थी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। संबंधित विभाग की ओर से सफाई और रखरखाव का कोई कार्य नहीं किया गया है। ट्रक पार्किंग के पास भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है जिससे यह समस्या और भी गंभीर हो गई है।

समस्या के बारे में जानकारी आपके द्वारा मिली है। जल्द ही साफ सफाई कराई जाएगी।
राधेश्याम, अवर अभियंता

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक:** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 । **Email:** swarajindia2023@gmail.com । **Mob:** 7800009853, । **Website:** www.swarajindianews.com । (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर कदम-कदम पर मौत के गड्ढे

» जिलाधिकारी की भी सुनने को तैयार नहीं एनएचएआई के अफसर

» सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मुद्दा उठने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर अफसर की अनदेखी से लगातार मौते ओर आये दिन कही न कही एक्सीडेंट हो रहे हैं लेकिन फिर भी अफसर सुनने को तैयार नहीं हैं। गड्ढों से भरा ये हाइवे ये कहने के लिए हाईवे हैं। मगर इस पर पिपरी भोगनीपुर से लेकर बारा जोड़ तक करीब 25 किलोमीटर का सफर खतरों से भरा है। कदम कदम पर मौत नाच

भोगनीपुर पुल के पास की फोटो

रही है हाईवे पर दो पहिया, चार पहिया वाहन सवारों को गड्ढों से बचने के लिए पैनी नजर रखनी पड़ती है। जरा सी नजर चूकते ही लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार मांग के बाद भी मरम्मत का काम एनएचएआई के जिम्मेदारों नहीं कराया।

सबसे खराब स्थिति कानपुर जाने वाले लेन की हैं। इस हाईवे पर पिपरी, भोगनीपुर, छतेनी,डींघ, देवीपुर, मावर, लालपुर के पास कई

बड़े गड्ढे हैं। इतना ही नहीं कई जगह सडक़ ओवरलोड वाहनों की वजह से दब गई है। हाईवे पर रात के अंधेरे में चलना खतरे से भरा रहता है।

हल्की बारिश होने पर गड्ढों में पानी भर जाता जिससे इनकी गहराई का अंदाजा नहीं रहता और वाहन सवार हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस सडक़ के मरम्मत के लिए स्थानीय लोग भी काफी समय से मांग उठा रहे हैं। इतना ही नहीं सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में भी सडक़ मरम्मत के

लिए मुद्दा उठा, मगर जिम्मेदारों ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। इस मामले में वहीं झांसी क्षेत्र के परियोजना निदेशक तरवीन शेरावत से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया है।

ग्राम नहोली में बना सचिवालय अपने हाल पर बहा रहा आंसू

नहोली पंचायत में तालेबंदी से शासन की मंशा पर फिर रहा है पानी

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। सरकार ने गांव-गांव तक प्रशासनिक सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से लाखों रुपए की लागत से ग्राम सचिवालयों का निर्माण कराया था, लेकिन सरवनखेड़ा ब्लॉक के नहोली ग्राम पंचायत का सचिवालय आज जनसेवा का केंद्र नहीं बल्कि निष्क्रियता और लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिवालय महीनों से बंद पड़ा रहता है। दरवाजों पर ताले जड़े हैं और सचिव अधिकांश कार्य घर से ही निपटा लेते हैं। शासन द्वारा चलाया गया सुविधा सबके द्वार अभियान यहां ताले के द्वार में बदल गया है।

गांव के लोगों का कहना है कि प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र या अन्य सरकारी कागजात के लिए उन्हें माती स्थित जनसेवा केंद्र तक जाना पड़ता है। यह न केवल समय और धन की बर्बादी है, बल्कि शासन की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने कहा, जिस भवन में सेवा की उम्मीद थी, वहां अब सन्नाटा गूंजता है। तालेबंदी हमारे हक पर ताला लगाने जैसी है।

धूल-जाले दे रहे सरकारी लापरवाही की गवाही

ग्रामीणों के अनुसार सचिवालय की दीवारों पर धूल की मोटी परत और दरवाजों पर मकड़ी के जाले साफ संकेत हैं कि यहां महीनों से कोई गतिविधि नहीं हुई। लोगों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च कर भी अगर सुविधा बंद दरवाजों के पीछे कैद है, तो यह योजना नहीं बल्कि विफलता का स्मारक है।

गांव वालों ने कहा, जनसेवा के 'श्मशान' बन जाएंगे सचिवालय

स्थानीय प्रशासनिक विशेषज्ञों और गांव वालों का कहना है कि शासन को तत्काल निगरानी बढ़ानी चाहिए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। अन्यथा ऐसे सचिवालय कुछ वर्षों में जनसेवा के श्मशान स्थल में बदल जाएंगे।

जहां शासन की गूंज उठनी थी, वहां अब खामोशी शासन कर रही है। नहोली पंचायत का यह बंद सचिवालय शासनिक उदासीनता का प्रतीक बन चुका है। ग्रामीण अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिला प्रशासन इस तालेबंदी को तोडक़र जनसेवा को फिर से जीवित करेगा।

जाम को मात देने वाले टीएसआई प्रदीप शर्मा बने इंस्पेक्टर

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। ट्रैफिक व्यवस्था में अनुशासन और दक्षता की मिसाल बन चुके तेज़तर्रार ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर (टीएसआई) प्रदीप शर्मा को अब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन मिला है। उनकी यह उपलब्धि न सिर्फ उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का परिणाम है,

बल्कि पूरे पुलिस विभाग के लिए गर्व का विषय भी है।

प्रदीप शर्मा ने कानपुर के कई व्यस्ततम चौराहों पर अपनी सेवा दी, जहां उन्होंने अपने कार्यकुशलता और सजगता से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखा। खास तौर पर घंटाघर चौराहा, जिसे कानपुर का दिल कहा जाता है और जहां अक्सर भारी जाम की स्थिति बनी रहती है, वहां उनके कार्यकाल के छह महीनों में एक भी दिन ट्रैफिक जाम नहीं लगा। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि जहां भी ड्यूटी मिले, वहां व्यवस्था और सेवा को प्राथमिकता दूं।

मैहर महोत्सव में दिखेगा जनसेवा और संस्कृति का अनोखा संगम

» आयोजक प्रमोद सिंह ने कहा अयोध्या बनेगी नई चेतना का केंद्र बिंदु

» 7-8 नवम्बर को अंतरराष्ट्रीय कुश्ती दंगल बनेगा आकर्षण का केंद्र

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या की पावन भूमि एक बार फिर सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक उत्सव की गूंज से भरने जा रही है। अपना दल (एस) के लोकप्रिय नेता एवं समाजसेवी प्रमोद सिंह की अगुवाई में 6 से 8 नवम्बर तक आयोजित होने वाला तीन दिवसीय मैहर महोत्सव नारी सम्मान, जनसेवा और खेल संस्कृति का अद्भुत संगम साबित होने जा रहा है। यह आयोजन उनके दिवंगत पिता पृथ्वी सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पित है, जिन्होंने समाजसेवा को जीवन का व्रत बनाया था।

महोत्सव का शुभारंभ नारी वंदन एवं अभिनंदन समारोह से होगा, जिसमें 21000 महिलाएं सामूहिक रूप से दुखदुरिया देवी की पूजा-अर्चना करेंगी।

यह दिन नारी के आत्मबल, सशक्तिकरण और सम्मान को समर्पित होगा। समारोह में उन महिलाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने शिक्षा, समाजसेवा, कला या जनकल्याण के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

प्रमोद सिंह का कहना है नारी शक्ति के बिना समाज अधूरा है। यह महोत्सव नारी सम्मान के प्रति हमारी आस्था और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। महोत्सव के अगले दो दिन खेल के रोमांच से सराबोर होंगे। ईरान, नेपाल, भूटान सहित कई देशों के अंतरराष्ट्रीय पहलवान मैहर महोत्सव कुश्ती दंगल में हिस्सा लेंगे। देश के शीर्ष पहलवानों के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच मिलेगा यह आयोजन न केवल खेल भावना को प्रोत्साहित करेगा बल्कि अयोध्या की मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय पहचान भी दिलाएगा।

बिना पद के लेकिन जनपद के जननायक

प्रमोद सिंह की पहचान केवल एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक कर्मशील समाजसेवी के रूप में है। उन्होंने बिना किसी पद के अयोध्या की जनता के बीच सेवा का जो सिलसिला शुरू किया है, वह लगातार जनविश्वास का रूप ले चुका है। उन्होंने विशाल खेल महोत्सव का सफल आयोजन। मेगा रक्तदान शिविर से जनजागरण। निःशुल्क शिक्षा अभियान से सैकड़ों गरीब छात्रों को नया जीवन। भारत आल्हा सम्राट प्रतियोगिता से लोकसंस्कृति का पुनर्जीवन। महाकाल तीर्थ यात्रा हर वर्ष श्रद्धालुओं के साथ उज्जैन दर्शन। रक्षा बंधन समारोह सैकड़ों बहनों के साथ रक्षाबंधन का सामाजिक पर्व। कंबल वितरण अभियान हजारों निराश्रितों तक सेवा की ऊष्मा प्रदान किया है। मैहर महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह समाज में नारी सम्मान, खेलप्रेम और सेवा संस्कार का जीवंत संदेश है। यह आयोजन अयोध्या को न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक ऊर्जा का भी केंद्र बना रहा है।

चित्रकूट कोषागार में हुए घोटाले की पूर्व सांसद ने उठाई जांच की मांग

पूर्व सांसद भैरो प्रसाद मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा

»स्वराज इंडिया ब्यूरो

चित्रकूट। चित्रकूट कोषागार घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है।

भाजपा के पूर्व सांसद भैरो प्रसाद मिश्र ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने कोषागार घोटाले के साथ-साथ जिले में चल रहे अन्य विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की भी जांच कराने की मांग की है। इस घोटाले में अब तक 43 करोड़ 13 लाख रुपये के गबन की पुष्टि हुई है।

जांच में खुलासा हुआ है कि मृत पेंशनरों के नाम पर फर्जी भुगतान किया गया। जिन पेंशनरों की मृत्यु हो चुकी थी, उनके नाम पर भी पेंशन और अन्य भुगतान जारी किए गए। करोड़ों रुपये के बिल फर्जी सत्यापन के जरिए पास किए गए, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। अब तक की जांच में 43 करोड़ 13 लाख रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। यह राशि 93 खातों के माध्यम से जारी की गई थी। इनमें से केवल तीन खातों से ही लगभग 10 करोड़ रुपये की निकासी दर्ज की गई है, मामले की गंभीरता को दर्शाता है।

97 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

इस मामले में चार कोषागार कर्मियों सहित कुल 97 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सहायक लेखाकार संदीप कुमार श्रीवास्तव भी आरोपितों में शामिल थे। पूछताछ से पहले उनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद से जांच और गहन हो गई है। जांच में वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह प्रश्न उठाया गया है कि मृत पेंशनरों के खातों में असामान्य राशि भेजे जाने पर अधिकारियों ने सत्यापन क्यों नहीं किया। जांच अधिकारी के अनुसार, यह मामला केवल मौजूदा चार कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पूर्व में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके।

हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया लंगड़ा

»स्वराज इंडिया ब्यूरो

उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र के करोवन मार्ग पर शुक्रवार देर रात पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी सज्जन राठौर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में एसओजी और सदर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की थी। पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने पुरानी रंजिश के चलते संजय सिंह की हत्या की थी। पुलिस फरार साथी की तलाश में दबिश दे रही है।

अलीगढ़ में मंदिरों की दीवारों पर लिखा आई लव मोहम्मद

» रणी सेना का हंगामा, पुलिस बल तैनात

»स्वराज इंडिया ब्यूरो

अलीगढ़। गांव भगवान पुर के दो और बुलाकगढ़ी के तीन मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा देखा गया। जिसकी जानकारी होने पर करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के साथ गांव में पहुंचे। पुलिस आनन-फानन मंदिरों पर लिखे आई लव मोहम्मद को मिटाने लगी तो कार्यकर्ता कार्रवाई नहीं होने तक नहीं मिटाने पर अड़ गए। अलीगढ़ के लोधा थाना अंतर्गत गांव भगवान पुर और बुलाकगढ़ी के पांच मंदिरों की दीवारों पर अराजकतत्वों ने आई लव मोहम्मद लिख दिया। जिसकी सूचना पर पहुंचे करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कई थानों का पुलिस बल भी वहां पहुंच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव भगवान पुर के दो और बुलाकगढ़ी के तीन मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा देखा गया। जिसकी जानकारी होने पर करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के साथ गांव

में पहुंचे। वहां पर गभाना थाने सहित कई थानों का पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस आनन-फानन मंदिरों पर लिखे आई लव मोहम्मद को मिटाने लगी तो कार्यकर्ता कार्रवाई नहीं होने तक नहीं मिटाने पर अड़ गए। पुलिस ने करणी सेना के कार्यकर्ता सचिन कुमार को हिरासत में लिया, जिससे और माहौल गरमा गया। बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने लोधा थाने में कार्रवाई के लिए पत्र भी दिया। थाना लोधा अंतर्गत आज प्रातः एक प्रकरण संज्ञान में आया कि एक देवस्थल पर कुछ धार्मिक नारे लिख दिये गये हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और धार्मिक नारों को तत्काल हटवाया गया। सभी जगह से नारे हटवा दिये गये हैं।

तिलोदकी गंगा में फिर बहेगी आस्था की धारा

» पत्रकार दुर्गा यादव बने आधुनिक भागीरथ, कोर्ट ने दिखाई सख्ती

» नगर निगम ने वर्ष 2022 में इस पवित्र धारा को बताया था नाला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।रामनगरी की पवित्र भूमि अब एक बार फिर अपनी प्राचीन सांस्कृतिक पहचान लौटाने की ओर अग्रसर है। सदियों से उपेक्षित तिलोदकी गंगा को नया जीवन देने की मुहिम आखिरकार रंग लाने लगी है। पत्रकार एवं समाजसेवी दुर्गा यादव के अथक प्रयासों से माननीय उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जिला प्रशासन को तीन माह के भीतर नदी को उसके मूल स्वरूप में लाने का आदेश दिया है।

इस फैसले ने न केवल अयोध्या में पर्यावरणीय चेतना को नई ऊर्जा दी है, बल्कि यह उदाहरण बन गया है कि एक सजग नागरिक की पहल से भी नदी, नारी और संस्कृति तीनों की गरिमा पुनर्जीवित की जा सकती है। जिला प्रशासन ने कोर्ट से छह माह का समय मांगा था, किन्तु न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा तीन माह में नदी दिखनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि नदी के मार्ग में किसानों की ज़मीन आती है तो उन्हें उचित मुआवज़ा देकर रास्ता साफ़ किया जाए। यह फैसला प्रशासनिक ढिलाई पर एक करारा संदेश है कि धार्मिक विरासतों के पुनर्जीवन में अब बहाने नहीं, केवल परिणाम चाहिए। बता दें कि तिलोदकी गंगा की कुल लंबाई लगभग 46 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की प्रत्येक नदी को पुनर्जीवित करने के निर्देश के बाद अब अयोध्या में इस दिशा में ठोस कदम उठने लगे हैं।

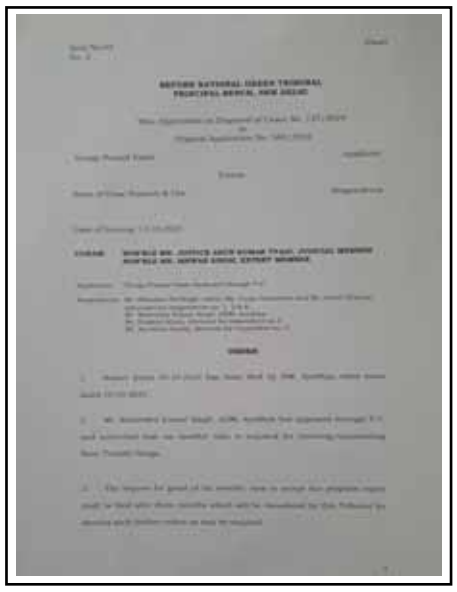

पत्रकार दुर्गा यादव बने आधुनिक भागीरथ

जहां शासन-प्रशासन ने वर्षों तक इस नदी की ओर आंखें मूंदे रखीं, वहीं दुर्गा यादव ने इसे जनांदोलन का रूप दिया। उनके सतत् प्रयासों, जन जागरण और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता ने न्यायालय को हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया। आज अयोध्या के लोग उन्हें आधुनिक भागीरथ कहकर सम्मानित कर रहे हैं।तिलोदकी गंगा का यह पुनरुद्धार केवल एक नदी की बहाली नहीं, बल्कि रामनगरी की आत्मा के पुनर्जागरण की कहानी है जहां आस्था और पर्यावरण दोनों मिलकर नई आशा का संचार कर रहे हैं।

तिलोदकी गंगा का गौरवशाली इतिहास

ऋषि रमणक की तपोभूमि से निकली यह नदी स्कंद पुराण में वर्णित है। इसके जल को तिल के समान श्यामल कहा गया, इसी कारण इसका नाम तिलोदकी पड़ा। सोहावल, मसौधा और पुरबाजार ब्लॉकों से होकर बहती यह नदी अंतत- सरयू में विलीन होती है। किंवदंती है कि कभी सिकंदर लोदी ने इस पर पुल बनवाया था, और आज यह नदी पुन- अपनी आध्यात्मिक धारा पाने को तत्पर है। नगर निगम ने वर्ष 2022 में इस पवित्र धारा को नाला बताकर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। परंतु आज वही धारा गंगा के सम्मान से पुकारे जाने लगी है। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागरण का प्रतीक है।

खाने के लिए मुर्गा दो वरना इलाका छोड़ दो!

अयोध्या पुलिस के सिपाही की फरमाइश से हिल गया महकमा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। कानून के रखवाले जब मुर्गे के लालची बन जाएं, तो समझिए पुलिस की नीयत और नीयम दोनों का कबाड़ा हो गया है। अयोध्या के कुमारगंज थाने में तैनात एक सिपाही पर आरोप है कि उसने एक घुमंतू जनजाति परिवार से खाने के लिए मुर्गा मांगा और इनकार करने पर इलाका छोड़ देने की धमकी दे डाली।

मसेढ़ा गांव के रहने वाले पिचाली, जो घुमंतू जनजाति से हैं, ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा सिपाही आशिक अली अपने साथी के साथ आया और कहा कि मुर्गा पकाओ, हम खाना चाहते हैं। मैंने कहा यह मुर्गा मेरी बेटियों ने पाला है, खाने के लिए नहीं दे सकते। बस, यही सुनते ही वह भड़क गया बोला, अगर यहां रहना है, तो मुर्गा देना पड़ेगा। इतना ही नहीं सिपाही ने पिचाली के बेटे अल्तीब का मोबाइल नंबर लिया और बार-बार फोन कर दबाव बनाया।मुर्गा दे दो, वरना देख लूंगा यह धमकी अब गांव-गांव चर्चा का विषय है।

पीड़ित पिचाली जब शिकायत लेकर कुमारगंज थाने पहुंचे, तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा यह स्टाफ का मामला है, बड़े साहब आएंगे तो देखेंगे। घंटों इंतज़ार के बाद थाना प्रभारी ओमप्रकाश पहुंचे। तब जाकर शिकायत ली गई। इस बाबत थानाध्यक्ष ओम प्रकाश ने कहा कि मामले की जांच कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

अयोध्या एयरपोर्ट पर नए निदेशक की नियुक्ति

» धीरेंद्र सिंह ने संभाला निदेशक पद का कार्यभार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या को नया निदेशक मिल गया है। श्री धीरेंद्र सिंह ने 22 अक्टूबर को हवाई अड्डा निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

कार्यभार संभालने से पहले श्री सिंह कांगड़ा एयरपोर्ट पर निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। एयरपोर्ट प्रबंधन, संचालन और यात्री सुविधा के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि उनके नेतृत्व में अयोध्या हवाई अड्डा नए विकास की उड़ान भरेगा। इस अवसर पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएनएस, एटीएस, फायर और टर्मिनल विभागों के प्रमुख अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सरकार का फैसला: पूरे प्रदेश में होगी नकली दवाओं की जांच

हर जिले में होगा औषधि नियंत्रण अधिकारी: सीएम योगी

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दवाओं की जांच जल्द हो सकेगी साथ ही नकली व गुणवत्ताविहीन दवाओं की बिक्री पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। दवाओं की कालबाजारी करने वालों खिलाफ जांच का दायरा बढ़ेगा। अब हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शुक्रवार को सहमति दे दी है।

प्रदेश में आए दिन नकली एवं गुणवत्ताविहीन दवाएं मिल रही हैं। इन दवाओं की जांच की जिम्मेदारी औषधि निरीक्षकों की है, लेकिन 13 जिलों में औषधि निरीक्षक ही नहीं। कई निरीक्षकों के पास दो-दो जिलों की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि नियंत्रण संवर्ग का होगा पुनर्गठन किया जाएगा। शुक्रवार को विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किया जाएगा।

यह औषधि निरीक्षकों की निगरानी करेगा। अभी तक औषधि निरीक्षक जिलाधिकारी से संबद्ध थे। इसी तरह उपायुक्त (औषधि) के पद भी बढ़ेंगे। अभी तक यह एक ही पद है। विभाग में अभी औषधि निरीक्षक के 109 पद हैं। इसमें 32 खाली हैं। ऐसे में औषधि निरीक्षकों का पद बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। उप आयुक्त से पदोन्नति पाने वाले संयुक्त आयुक्त (औषधि) के पद पर तैनाती दी जाएगी। इसके लिए अर्हकारी सेवा में संशोधन होगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी

नोएडा, स्वराज इंडिया ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं । वह अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद उद्घाटन की तारीख पर मुहर लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। एयरपोर्ट के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो गया है। शुरुआत में सालाना 50 लाख यात्री आने का अनुमान है।

इसके अलावा एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग और पार्किंग की भी तैयारियां की जा रही हैं। दो दिन पहले ही यात्रियों के आगमन और विमान सेवाएं शुरू करने का सफल ट्रायल भी किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को भी यह ट्रायल किया जाएगा।

पांच मंदिरों की दीवारों पर लिखा आई लव मोहम्मद!

करणी सेना ने काट दिया बवाल, मचा हंगाम

अलीगढ़

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

अलीगढ़। यूपी के अलीगढ़ जिले के थाना लोधा इलाके के बुलाकी गढ़ी गांव सहित कई गांवों के मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। जिले की फिजा और माहौल बिगड़ने के उद्देश्य से मंदिरों पर लिखा गया। शरारती तत्वों के द्वारा मंदिरों पर लिखा गया। आई लव मोहम्मद लिखने की सूचना पर गांव में करणी सेना के लोग पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग करने लगे।

अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के बुलाकी गढ़ी गांव में करणी सेना ने पुलिस पर मंदिर पर लिखे गए आई लव मोहम्मद को मिटाने का आरोप लगाया। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान के नेतृत्व में बड़ी तादाद में करणी सैनिक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, बुलाकी गढ़ी गांव पहुंच गए।

वहीं पुलिस स्थानीय लोगों को समझने का प्रयास कर रही है। वही करणी सेना ने पुलिस पर मंदिर पर लिखे गए आई लव मोहम्मद को मिटाने का आरोप लगाया। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान के नेतृत्व में बड़ी तादात में करणी सैनिक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, बुलाकी गढ़ी गांव पहुंच गए।वही करणी सेना ने यह भी आरोप लगाया है कि गांव एक मौलवी है उसकी सरपरस्ती में यह हो रहा है। लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। उल्टा हमारे ही लोगो को रोक रही और बंद कर रही है।

वही इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चार-पांच जगह मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखे हुए पाए गए हैं। पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था के मध्य नजर उनको मिटवा दिया गया है। इस मामले में जो भी तहरीर प्राप्त होगी इस आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं,जल्द ही खुलासे का प्रयास कर रहे हैं।

69000 शिक्षक भर्ती: अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, की नारेबाजी

बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरकर आत्मदाह की चेतावनी

कहा- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में शनिवार को 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी को फिर से ईको गार्डन भेज दिया।

69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण में भेदभाव को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कई महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी वह मंत्री संदीप सिंह और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास का घेराव कर चुके हैं। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में हैं। लेकिन, सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से हमारा पक्ष नहीं रख रही है।

इसी को लेकर धनंजय गुप्ता के नेतृत्व में अभ्यर्थी एक बार फिर मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे। वहां नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार सेकंड पार्टी है। वह हम लोगों का पक्ष मजबूती से रखे। अन्यथा हम सब लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। प्रदर्शन कर रहे धनंजय गुप्ता, रवि पटेल, अमित मौर्य ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी। इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया। लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया। अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। लेकिन, सरकार हीला हवाली करती रही।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि 28 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भेजे। हमारे पक्ष में सुनवाई करा कर हमें न्याय दिलाए। अब तक लगभग 22 से अधिक तारीखें मिलीं, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। इससे सभी अभ्यर्थी परेशान हैं।

पुलिस ने अभ्यर्थियों को लखनऊ पहुंचने से रोका

शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी उमाकांत मौर्य ने बताया कि अम्बेडकर नगर से आ रहे अभ्यर्थियों को रात में पुलिस ने घर व रास्तों में ही रोक लिया। इससे लखनऊ में अभ्यर्थियों की संख्या कम रही। पुलिस कई अभ्यर्थियों को फोन करके उनकी जानकारी जुटाती रही। डर और भय के कारण भी कुछ अभ्यर्थी लखनऊ नहीं पहुंच पाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पुलिस के माध्यम से उनके आंदोलन को सरकार कुचलने का प्रयास कर रही है।